GRT

GOLDEN RESEARCH THOUGHTS

ISSN: 2231-5063
IMPACT FACTOR : 4.6052 (UIF)
VOLUME - 11 | ISSUE - 3 | SEPTEMBER – 2021

हिन्द प्रशांत क्षेत्र और ऑकस समझौता भारत के विशेष संदर्भ में

डॉ. मनीष कुमार साव
सहायक प्राध्यापक– राजनीतिविज्ञान,
शास.एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा (छ.ग.)

संदर्भ

ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने हाल ही में एक त्रिपक्षीय समझौते की घोषणा की है, जिसे ऑकस (AUKUS) का संक्षिप्त नाम दिया गया है। हालॉकि फ्राँस ने इस परमाणु गठबंधन का विरोध किया है। इस गठबंधन की घोषणा करते हुए चीन का नाम लिये बिना अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से उभर रहे खतरों से निपटने के लिये अमेरिका और ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया के साथ कृत्रिम बुद्धिमता, साइबर–वारफेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग एवं परमाणु पनडुब्बी निर्माण जैसे क्षेत्रों में खुफिया एवं उन्नत तकनीक साझा करेगें।

'AUKUS' के गठन के पक्ष में तर्कः–

आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा घोषित इस गठबंधन को एशिया–प्रशांत क्षेत्र के लिये एक ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते के रूप में देखा जा सकता है, जो चीन का मुकाबला करने के एक प्रयास के रूप में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। यह आस्ट्रेलिया को पहली बार अमेरिका द्वारा प्रदान की गई प्रौद्योगिकी का उपयोग कर परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों के निर्माण में सक्षम करेगा। ये तीनो राष्ट्र पहले से ही एक–दूसरे से संबद्ध रहे है। अमेरिका और ब्रिटेन नाटो सहयोगी है, जबकि आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका 'ANZUS' समझौते से एक–दूसरे से संबद्ध है। तीनों राष्ट्र फाईव–आई (Five-Eyes) इंटेलिजेंस गठबंधन के भी सदस्य है। हालॉकि इस घोषणा ने इस मंच की भविष्य की प्रासंगिकता और इसके दीर्घकालिक अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है क्योकि हिन्द–प्रशांत क्षेत्र के लिये पहले ही क्वाड्रीलेटरल सिक्यूरिटी डायलॉग (QUAD) की स्थापना की जा चुकी है। इस विस्तृत स्तर के गठबंधन में पूर्व की तुलना में कमजोर पोस्ट ब्रेग्जिट ब्रिटेन को शामिल करना भी आलोचना का शिकार हो सकता है।

क्वाड और हिन्द प्रशांत क्षेत्र पर प्रभाव :–

इस बात की आशंका प्रकट की जा रही है कि (AUKUS) अमेरिका–यूरोपिय संघ के संबंधों एवं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को कमजोर कर सकता है। आरंभिक प्रतिक्रिया के तौर पर फ्राँस ने संयुक्त राष्ट्र में आस्ट्रेलिया, फ्राँस और भारत के

विदेश मंत्रियों की एक निर्धारित बैठक को रद्द कर दिया है। पिछले कुछ वर्षो से एक उभरती हुई हिन्द–प्रशांत संरचना में यह त्रिपक्षीय संलग्नता एक महत्वपूर्ण तत्व बन गई थी। इस प्रकार बैठक का रद्द किया जाना त्रिपक्षीय संलग्नता पर प्रतिकुल प्रभाव डालेगा। अभी यह स्पष्ट नही है कि क्वाड और AUKUS एक–दूसरे को सुदृढ़ करेंगे या परस्पर अनन्य बने रहेंगें। कुछ ऐसी मान्यताएँ भी है कि एंग्लोस्फीयर राष्ट्रो यानी आंग्ल प्रभाव क्षेत्र के राष्ट्रों (Anglosphere nations)– जो ब्रिटेन के साथ साझा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक संबंध रखते है, के बीच एक–दूसरे को लेकर अधिक भरोसा है।

भारत पर प्रभाव :–

भारत का बहिर्वेशन : AUKUS का निर्माण चीन को एक कड़ा संदेश भेजने का प्रयास है। हालाँकि चीन द्वारा इस गठबंधन को एक बहिर्वेशनकारी मंच (Exclusionary Bloc) कहा जाना क्वाड तथा मालाबार फोरम के दो सदस्यों भारत और जापान के लिये भी मंथन का विषय है, जिन्हे नए समूह से बाहर रखा गया है।

हिन्द प्रशांत क्षेत्र में नेतृत्व के लिये अमेरिका के नये भागीदार :

भारत अमेरिका सुरक्षा संबंधों की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ – वर्ष 2008 में भारत–अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते, पर हस्ताक्षर, वर्ष 2012 में रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल की शुरूआत, वर्ष 2016 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा भारत को प्रमुख रक्षा सहयोगी का दर्जा प्रदान करना, भारत को टियर–1 का दर्जा प्रदान करना जो उसे उच्च–प्रौद्योगिकी वस्तुओं के निर्यात में सक्षम बनाता है, और वर्ष 2018 में दोनो देशों के बीच 2+2 वार्ता की शुरूआत।

वर्ष 2020 में चौथे तथा अंतिम संस्थापक समझौते (Foundational) पर हस्ताक्षर के साथ यह माना गया कि दोनो देशों के बीच करीबी रक्षा संबंध के मार्ग की अंतिम बाधा भी दूर कर ली गई है। लेकिन AUKUS की स्थाना के साथ यह आशंका प्रबल हुई है कि संभवतः यह अमेरिका नीति में पुनः परिवर्तन की शुरूआत है, जहॉ हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में नेतृत्व के लिये आस्ट्रेलिया के रूप में एक नए साथी की खोज की जा रही है।

चीन की प्रतिक्रिया :–

चीन ने दुनिया भर के देशों से 'आधिपत्य और विभाजन' का विरोध करने का आव्हान किया है। चीन ने स्पष्ट किया है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने वाले, संघर्ष पैदा करने वाले और तथा कथित नियम निर्धारण के बैनर तले विभाजन पैदा करने वाले ऐसे कृत्यों का विरोध करता है। वही चीन स्वयं कृत्रिम् द्वीपों का निर्माण करने और उन्हे दुर्गीकृत हवाई ठिकानों में बदलने की राह पर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका और सहयोगी देशों की नौसेनाओं द्वारा नियमित रूप से ''नौवहन की स्वतंत्रता'' अभियानों का कार्यान्वयन न तो चीन को रोक सका है, न ही उसे निरूत्साहित कर सका है। चीन ने भारतीय सीमा पर इससे भी अधिक आक्रामक रूख अपनाया है, जहाँ उसने भारतीय क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पद दावा जताने के लिये व्यापार पैमाने पर सैन्य तैनाती का इस्तेमाल किया है और इसके कारण जून, 2020 से संघर्ष की भी स्थिति बनी हुई है। भारत, निसंदेह एक बड़ी काफी कीमत पर, जवाबी कार्यवाही करते हुए अपनी जमीन पर खड़ा रहा है। इस खतरनाक टकराव के अभी जारी बने रहने की संभावना है। क्वाड ने, संभवतः इस भय से कि उसे 'एशियाई नाटो' करार दिया जाएगा, न तो कोई चार्टर बनाया है और न ही किसी उल्लेखनीय तरीके से कोई कदम आगे बढ़ाया है। दूसरी ओर, चीन ने क्वाड को यह कहकर खारिज करने का प्रयास किया है कि यह ''सुर्खियाँ बटोरने वाला एक विचार है जो जल्द विलुप्त हो जाएगा।''

आगे की राह :–

जबकि भारत–अमेरिका संबंधों की में हो रही बढ़ोतरी भारतीयों के लिये राहतमंद है, किन्तु भारत को इस द्विपक्षीय आख्यान में अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अस्पष्ट वास्तविकताओं के प्रति सतर्क बने रहना चाहिये। 'भारत को एक महान शक्ति बनाने के लिये' सहायता करने के अमेरिका प्रस्ताव और इस घोषणा कि 'दुनिया के दो महान लोकतंत्रों के पास दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएँ भी होनी चाहिये' को अति–उत्साह से ग्रहण नही किया जाना चाहिये और इन शांतिपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिये। माना जाता है कि चीन ने अपनी स्थिति को पिछले 30 वर्षों में अमेरिका द्वारा प्रदत्त या चोरी की गई उत्पन्न प्राद्यौगिकी से काफी मजबूत किया है। भारत को अपनी 'रणनीतिक साझेदारी' दर्शाने हेतु अमेरिकी कंपनियों से लगभग 22 बिलियन डॉलर के सैन्य हार्डवेयर की खरीद करनी पड़ी है जो 'आत्मनिर्भरता' और 'बाह्य निर्भरता से मुक्ति' के भारतीय लक्ष्य के दृष्टिकोण से एक विशिष्ट प्रतिगामी कदम है। हमें स्टील्थ फाइटर्स, जेट इंजन, उन्नत रडार और पनडुब्बियों के साथ–साथ विमान–वाहकों के लिए परमाणु प्रणोदन सहित ऑस्ट्रेलिया को प्रदान की जा रही सभी प्रद्यौगिकियों (उनके सौद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान सहित) की भी आवश्यकता है। अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिये भारत को एकाधिकारवाद के विरूद्ध सुरक्षा के साथ ही अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली के लिये पर्याप्त समय या अवसर की आवश्यकता होगी। यह राहत उसे उन्नत प्रद्यौगिकी तक पहुँच बनाने और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने में सक्षम बनायेगी। अपने स्वयं के संघर्षो से जूझने की तैयारी करते हुए भारत को बाहरी संतुलन की तलाश करने की आवश्यकता होगी। 'वास्तविक राजनीति' (Realpolitik) की माँगों और आवश्यकताओं के अनुरूप उसे पुरानी धारणाओं को तोड़ने और नई साझेदारियों में प्रवेश करने की भी आवश्यकता है।

फ्राँस और यूरोप के साथ मजबूत संबंध का निर्माण करना :–

लंबे समय तक यूरोप के लिये राजनयिक रूप से गतिहीन क्षेत्र ही रहा था। भारत ने जब से यह समझा कि छोटे से लक्जमबर्ग से लेकर उभरते हुए पोलैंड तक प्रत्येक यूरोपीय राष्ट्र के पास भारत के लिये बहुत कुछ है, तब से यूरोप भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख केन्द्र बन गया है। पिछले कुछ वर्षो से फ्राँस के साथ भारत की रणनीतिक भागीदारी में तेजी आई है। उदाहरण के लिये भारत सरकार ने हिन्द महासागर की सुरक्षा के मामले में फ्राँस के साथ मिलकर कार्य करने की दिल्ली की पूर्व की अनिच्छा का त्याग कर दिया है। पिछले कुछ वर्षो में भारत ने ब्रिटेन के साथ एक नई साझेदारी के निर्माण का प्रयास किया है, जो विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक प्रमुख वित्तीय केन्द्र एवं एक प्रौद्योगिकी शक्ति है और वैश्विक मामलों में काफी महत्वपूर्ण है।
भारत को निम्नलिखित बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है :– सर्वप्रथम भारत को फ्राँस, ऑस्ट्रेलिय, ब्रिटेन और अमेरिका को याद कराना होगा कि हिन्द–प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में उनके साझा हित निहित हैं और आपसी झगड़े से इस बड़े लक्ष्य को कमजोर करने का खतरा है। दूसरा, हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में प्रभावी निरोध के लिये भू–भाग की विशाल आवश्यकताओं को उजागर करना और यह ध्यान दिलाना कि 'AUKUS' द्वारा रेखांकित किये गए सभी क्षेत्रों (प्रभावी अंतर्जलीय क्षमताओं से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर वारफेयर तक) में उच्च प्रौद्योगिकी तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग के विकास हेतु अतिव्यापी गठबंधनों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस और अन्य यूरोपीय देशों के लिये हिन्द–प्रशांत भागीदारों के साथ सहयोग करने के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं।

निष्कर्ष :–

भारत के हित फ्राँस और यूरोप के साथ–साथ क्वाड और 'एंग्लोस्फीयर राष्ट्रो' के साथ भी गहन रणनीतिक सहयोग में निहित हैं। हिंद–प्रशांत गठबंधन में विभाजन को रोकने के लिये पश्चिम के साथ भारत के विविध संबंधों का पूर्ण लाभ उठाया जाना चाहिये।

संदर्भ सूची :–

1} पंत पुष्पेश और जैन, श्रीपाल ''प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ'' मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ 2016
2} जौहरी जे.सी., ''विश्व राजनीति के बदलते आयान'' जालन्धर 2016
3} यादव डॉ. आर.एस., ''भारत की विदेश नीति : एक विश्लेषण'' किताब महल इलाहाबाद 20012
4} फड़िया बी.एल. ''अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत व मुख्य मुद्दे'' आगरा 2018
5} दीक्षित जे.एन. ''इण्डियाज फारेन पॉलिसी'' प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली 2003